भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 954

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता

954. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद 2023-24 में यूरिया का आयात 70.42 लाख टन ही था, क्या वित्त वर्ष 2025-26 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त के लक्ष्य हेतु प्रयास किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चूंकि गत वर्ष 106 लाख टन से अधिक का आयात किया गया था और एमओपी का थोड़ा भी घरेलू उत्पादन नहीं हुआ था, फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विगत दो वर्षों में समग्र उर्वरक उत्पादन में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि के बाबजूद आयात पर निर्भरता बनी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तालचेर, गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी और रामागुंडम सहित देश भर में उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार संबंधी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) प्रत्येक परियोजना पूरी तरह से कार्यशील होने पर आयात प्रतिस्थापन में अनुमानत: कितना योगदान देगी; और

(च) रॉक फॉस्फेट और पोटाश जैसे कच्चे माल के भारी आयात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इनपुट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है, जिसके बिना उर्वरक आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधीर ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

(आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.03.2025 को ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने पर, देश में यूरिया का उत्पादन 25.4 एलएमटीपीए तक बढ़ जाएगा तथा इससे यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था जो वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी का रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

(ख) और (ग): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में पोटाश का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और भारत अपनी पोटाश की आवश्यकता के लिए 100% आयात पर निर्भर है। अत: सरकार ने शीरे से व्युत्पन्न पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, को दिनांक 13.10.2021 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) व्यवस्था के तहत अधिसूचित किया है। इसके अलावा, आयातित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई/संज्ञान में लिया गया है।

(ii) उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 में 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है। जोड़े गए 06 नए ग्रेड एनपीके 08-21-21, एनपीके 09-24-24, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) (0-0-14.5-0), मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन और सल्फर से संपुष्ट एनपीके 11-30-14, यूरिया-एसएसपी कॉम्प्लेक्स 5-15-0-10 और मैग्नीशियम, जिंक और बोरॉन से संपुष्ट एसएसपी 0-16-0-11 हैं।

(iii) एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी, मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

(घ) और (ङ.): देश में स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने प्रत्येक 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की स्थापना के लिए नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तालचेर (ओडिशा) इकाइयों तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई को पुनर्जीवित करने के अधिदेश दिए। रामागुंडम और गोरखपुर इकाइयों को क्रमशः दिनांक 22.03.2021 और दिनांक 07.12.2021 को शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः दिनांक 18.10.2022 और दिनांक 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। इन संयंत्रों ने देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन को 50.8 एलएमटी प्रति वर्ष बढ़ाया है। वर्तमान में तालचेर इकाई निष्पादन स्तर के अधीन है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.03.2025 को ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना की समाप्ति पर, देश में यूरिया का उत्पादन 25.4 एलएमटीपीए तक बढ़ जाएगा तथा इससे यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने में मदद मिलेगी।

(च): सरकार देश में रॉक फॉस्फेट और पोटाश जैसे कच्चे माल के आयात को बढ़ाने के लिए संसाधन समृद्ध देशों के साथ लगातार चर्चा कर रही है। सरकार देश में कच्चे माल की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक समझौतों (एलटीए/समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की भी सुविधा प्रदान करती है। रॉक फॉस्फेट के मामले में, भारतीय कंपनियों ने वर्तमान में मोरक्को से 16,00,000 से 18,00,000 मीट्रिक टन (एमटी), जॉर्डन से 5,00,000 मीट्रिक टन, टोगो से 2,40,000 मीट्रिक टन और मॉरिटानिया से 1,50,000 मीट्रिक टन की वार्षिक आपूर्ति के लिए समझौते/समझौता ज्ञापन किए हुए हैं। पोटाश के लिए, भारतीय कंपनियों ने रूस से 6,50,000 मीट्रिक टन, बेलारूस से 6,00,000 मीट्रिक टन और जॉर्डन से 1,25,000 मीट्रिक टन के लिए वार्षिक आपूर्ति समझौते/समझौता ज्ञापन किए हैं।

****